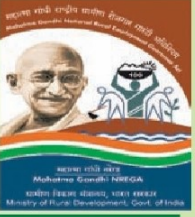


# ग्रामीण विकास विभाग तथा पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार सरकार



महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत “वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान”  
01 से 10 अगस्त 2018 – 50 लाख पौधे रोपने का कार्यक्रम



**श्री नीतीश कुमार**  
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

**मुख्य समारोह**

जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तर पर

(प्रखंड मुख्यालय या किसी एक ग्राम पंचायत के किसी एक स्थान पर)



**वृक्ष से जल और जल से जीवन  
आओ सभी मिलकर वृक्ष लगायें**

**सभी ग्राम पंचायत में सघन वृक्षारोपण अभियान**

## सरकारी भूमि पर सामाजिक वानिकी

- 200 पौधों की एक इकाई
- वन विभाग की नर्सरी से निर्धारित दर पर पौधे प्राप्त किये जा सकते हैं
- प्रत्येक इकाई पर दो वन पोषक
- प्रत्येक वनपोषक को 7 रुपये प्रति जीवित पौधों की दर से 1400 रुपये प्रति माह – पांच वर्षों के लिए।

### वनपोषकों के लिए शर्त

- ✓ वन पोषक हेतु आवेदन अपने निवास के ग्राम के राजस्व सीमा के अंतर्गत ही किया जा सकता है
- ✓ वृक्षारोपण स्थल से दूरी के आधार पर आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी
- ✓ दिव्यांगों, एकल महिला परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों एवं जीविका की महिला सदस्यों को योजना में शामिल होने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी

### वन पोषक के अधिकार

पांच वर्ष के बाद प्रत्येक वन पोषक परिवार को 50-50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत वृक्ष पट्टा के रूप में दिया जायेगा जिससे वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल, फूल, आदि का लाभ मिलेगा

## निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी

- लाभुकों की स्वयं की भूमि पर 200 पौधों की एक इकाई का वृक्षारोपण
  - लाभुक के पास पर्याप्त भूमि नहीं होने पर 2 या 3 किसानों की भूमि मिलाकर भी 200 पौधे लगाए जा सकते हैं
  - लाभुक के पसंद के काष्ठ / फलदार पौधे लगाये जायेंगे
  - पौधों की सुरक्षा के लिए बांस गैबियन का प्रावधान
  - पौधों के पटवन हेतु चापाकल अथवा पानी टंकी-सह-दाली का प्रावधान
  - 200 पौधों की प्रत्येक इकाई पर लाभुक परिवार के एक सदस्य को वन पोषक बनाया जायेगा – पांच वर्षों के लिए
  - वन पोषक को 7 रुपये प्रति जीवित पौधों की दर से 1400 रुपये प्रति माह – पांच वर्षों के लिए
  - वृक्षों के उपर लाभुक का पूर्ण अधिकार
- मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि पर वृक्षारोपण की अनुमान्यता**
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
  - गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
  - भूमि सुधार के लाभार्थी (पर्चधारी)
  - इंदिरा /प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी
  - अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के अधीन लाभार्थी
  - लघु या सीमांत कृषक



सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से अनुरोध है कि मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी हेतु वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान में भाग ले कर इसे सफल बनायें।

अवेध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।